भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 318

05 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन में वृद्धि

318. डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वर्ष 2019 से इस्पात उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य इस्पात उत्पादक देशों की तुलना में भारत के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस्पात उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क)और(ख): जी हाँ। भारत ने वर्ष 2019 से इस्पात उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की है। पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक कच्चे इस्पात के उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

वित्तीय वर्ष	**कच्चा इस्पात उत्पादन (एमटी)**
2018-19	110.92
2019-20	109.14
2020-21	103.54
2021-22	120.29
2022-23	127.20
स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी = मिलियन टन	

(ग): भारत जापान को पीछे छोड़कर वर्ष 2018 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है और तब से वहीं बरकरार है। कैलेंडर वर्ष 2022 में विभिन्न देशों का कच्चे इस्पात का उत्पादन निम्नानुसार है:-

देश	**कच्चा इस्पात उत्पादन (मिलियन टन में) कैलेंडर वर्ष 2022**
चीन	1019.1
भारत	125.4
जापान	89.2
संयुक्त राज्य	80.5
रूस	71.7
स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)	

जारी 2

(घ): इस्पात एक नियंत्रण-मुक्त क्षेत्र है, सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के वांछित अनुमानों को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:-

i. सरकारी खरीद के लिए मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन करना ।
ii. देश के भीतर विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की अधिसूचना जारी करना।
iii. देश में इस्पात क्षेत्र में इस्पात के उपयोग, इस्पात की समग्र मांग और निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संभावित उपयोगकर्ताओं के साथ और अधिक भागीदारी के साथ मेक इन इंडिया पहल और पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान शुरू करना।
iv. भारत के इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कुछ इस्पात उत्पादों पर व्यापार सुधारात्मक उपायों के केलिब्रेशन के साथ-साथ इस्पात उत्पादों और कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क में समायोजन।
v. अधिक अनुकूल शर्तों पर इस्पात निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की सुविधा के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय करना।

****